सिंहावलोकन

साझा नजरिया

''राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश ने अपना कार्यभार संभालने से काफी पहले भारत के साथ रिश्ते सुधारने का लक्ष्य तय कर लिया था: भारत एक अरब से ज्यादा लोगों का राष्ट्र; एक गतिमान, बहु-नस्लीय लोकतंत्र; अमेरिका में बसे 15 लाख लोगों का पुश्तैनी घर; जिसका एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है; अनेक उपलब्धियों और संभावनाओं वाला एक राष्ट्र है। नवंबर, 2001 में राष्ट्रपति बुश से पहली मुलाकात में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और अमेरिका को 'स्वाभाविक साथी' करार देते हुए हमारे दोतरफा रिश्तों को नया स्वरूप देने के लक्ष्य को अंगीकार किया, तो वे ठीक ही कह रहे थे। हमारे दोनों देश मानव ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करना और 21वीं सदी के विश्व के अवसरों को समेटना चाहते हैं। और हम दोनों देश इस बात को मानते हैं कि हमारे सहयोग से दोनों ही राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को काफी लाभ हो सकता है।''

—**कोलिन एल. पॉवेल,** विदेश मंत्री, मार्च 2004

भारत जब मई 1998 में परमाणु संदेहों में से धमाकेदार तरीके से बाहर निकला तो कोई आशावादी भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि पोखरण परीक्षणों के बाद हुई प्रतिक्रिया कुछ ही वर्षों में ऐसी निर्णायक शक्ल ले लेगी, कि अमेरिका और भारत परमाणु प्रौद्योगिकी के नागरिक इस्तेमाल, अंतरिक्ष, उच्च प्रौद्योगिकी के कारोबार और मिसाइल प्रतिरक्षा के क्षेत्र में साथ-साथ काम करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

भारत और अमेरिका के बीच उच्च प्रौद्यौगिकी व्यापार को बढ़ावा देने संबंधी 2004 के समझौते, जिसे 'रणनीतिक साझेदारी की दिशा में अगला कदम' (एनएसएसपी)

मिरिएम कारावेल्ला

विदेश मंत्री कोलिन एल. पॉवेल एक टीवी संवाद के दौरान नई दिल्ली में विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करते हुए

ठीक ही कहा गया है, इससे परमाणु ऊर्जा के नागरिक इस्तेमाल, नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार और मिसाइल प्रतिरक्षा पर बातचीत जैसे चार क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। लेकिन इससे भी अहम यह कि इससे भारत-अमेरिकी संबंध रणनीतिक स्तर पर पहुंचे हैं और इससे यह भी जाहिर होता है कि दोनों देश किस हद तक साथ-साथ आगे बढ़े हैं। कुछ साल पहले, भारत की उच्च अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच मना थी और नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले इस क्षेत्र को फिर से खोलने के लिए दोनों देशों को कई साल तक जटिल बातचीत करनी पड़ी थी।

भारत और अमेरिका के संबंधों में परिवर्तन अलग-अलग रुख रखने वाले दो लोकतंत्रों के मित्र देश बनने की कहानी है, जो समान मूल्यों और साझा हितों पर आधारित विश्व में नए अवसरों के सृजन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत डेविड सी. मलफोर्ड ने कहा है: ''पिछले दो वर्षों में हम इस परिवर्तन की शुरुआत के गवाह रहे हैं। इससे हमारे दोनों देशों के लिए ऐसे अवसर खुलेंगे, जो कुछ साल पहले तक कल्पना से बाहर की बात थे। हमने पिछले अविश्वासों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और ऐसा आधार तैयार किया है, जिसके बारे में मेरा मानना है कि इस पर 21 वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण साझीदारी तैयार होगी।'' उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को सही मायने में ऐसे व्यापक गठजोड़ के रूप में विकसित किए जाने की जरूरत रेखांकित की, जिससे दोनों देशों के समाज के सभी क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिले। और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा: ''भिन्न स्थितियों वाले, मगर मजबूत द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े दो सबसे बड़े लोकतंत्रों, जो निरंतर समान रूप से सामने आती चुनौतियों से निबटने के लिए अलग-अलग समझ से काम कर रहे हैं, का दृष्टिकोण वैश्विक मामलों में रोमांचक संभावना जगाता है।''

भारत-अमेरिकी संबंधों के इस कायापलट का एक निर्देशक दस्तावेज अमेरिका की सन् 2002 की नेशनल सिक्यूरिटी स्ट्रेटेजी है, जिससे भावी सहयोग का रास्ता खुलता है: ''अमेरिका ने भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में बदलाव

को इस मजबूत विश्वास के आधार पर अंगीकार किया है कि अमेरिकी हितों को भारत के साथ मजबूत संबंधों की दरकार है। हम दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जो प्रतिनिधि सरकार के जरिए संरक्षित राजनैतिक आजादी के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत बड़ी आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में भी बढ़ रहा है। वाणिज्य के मुक्त प्रवाह में, जिसमें हिंद महासागर के अहम सामुद्रिक रास्ते से कारोबार भी शामिल है, हमारे समान हित हैं। अंततः आतंकवाद से लड़ने और रणनीतिक रूप से स्थिर एशिया बनाने में हमारे साझा हित हैं।''

सन् 1998 के परमाणु परीक्षणों ने भारत-अमेरिकी संबंधों को निचले स्तर पर पहुंचा दिया था और उन्हें उबारने के लिए मजबूत राजनैतिक तथा आर्थिक पहल करना अपरिहार्य था। ऐसी पहल भारत के पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह और अमेरिका के पूर्व उप-विदेश मंत्री स्ट्रोब टालबोट के बीच हुई नौ दौर की वार्ता के दौरान तैयार हुई। इससे न केवल भारत सरकार परमाणु अप्रसार पर अमेरिकी चिंताओं के प्रति संवेदनशील हुई बल्कि भारत को भी अपने अलिखित रणनीतिक सिद्धांत और अपनी सुरक्षा चिंताओं के अनेक अहम पहलू अमेरिका को समझाने का मौका मिला। साल भर चली उन वार्ताओं का एकमात्र महत्व तो यही था कि ये वार्ताएं भारत-अमेरिकी संबंधों के भविष्य के लिए नई लीक रचने वाली साबित हुईं। लगभग आधी शताब्दी तक एक-दूसरे के ''खिलाफ'' बात करने वाले भारत और अमेरिका एक-दूसरे के साथ बातचीत करने के अभ्यस्त हुए। जैसा कि टालबोट ने कहा, ''हम बिना असहमत हुए असहमति से ऊपर उठे हैं।'' दोनों देशों के इतिहास में यह पहला अवसर था जब दोनों में सबसे लंबी उच्चस्तरीय वार्ता चली।

इस समझ का नतीजा यह निकला कि अमेरिका ने पहले अपने वे प्रतिबंध ढीले किए जो परीक्षणों के बाद भारत के खिलाफ कस दिए गए थे। हालांकि जसवंत-टालबोट वार्ता एक साधारण मसले पर लड़खड़ाई: अक्तूबर '99 में अमेरिकी सीनेट में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) को मंजूरी देने का प्रस्ताव गिर जाने के बाद भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर करने में हिचकिचाहट दिखाई। अमेरिका ने भी भारत को उच्च-प्रौद्योगिकी के मुक्त निर्यात से हाथ खींच लिए।

नरेंद्र विष्ट/इंडिया टुडे

भारतीय अर्थव्यवस्था के नए स्वरूप के रचयिता डॉ. मनमोहन सिंह आज प्रधानमंत्री के रूप में कमान थामे हुए हैं

फिर भी, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मार्च 2000 में भारत यात्रा, भारत-अमेरिकी संबंधों को प्रगाढ़ता देने वाली थी। भारतीय संसद के दुर्लभ संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए क्लिंटन ने भारत द्वारा दुनिया को सिखाए गए सबकों का जिक्र किया: ''पहला सबक लोकतंत्र के बारे में है। अभी भी ऐसे कई हैं जो लोकतंत्र को सार्वभौमिक महत्वाकांक्षा नहीं मानते; जो यह कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ किसी खास संस्कृति के लोगों के लिए या थोड़ा-बहुत आर्थिक विकास करने के लिहाज से ही कारगर है। भारत उन्हें पिछले 52 साल से गलत साबित करता रहा है....दूसरा सबक, जो भारत सिखाता है, वह विविधता का है.... कठिन हालात में भी आपने दुनिया को दिखा दिया है कि मतभेदों के साथ कैसे रहा जा सकता है...कि सहिष्णुता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान कई तरह से हमारे समान अस्तित्व की कुंजी है।''

भारत-अमेरिकी संबंधों के बदलाव की प्रक्रिया बुश प्रशासन के दौरान तेज हुई। नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के शुरू में ही ''बड़े संबंधों को ठीक करने'' का फैसला किया और भारत को भी उनमें शामिल किया। नए विश्व की व्यापक रणनीतिक तस्वीर में भारत की बढ़त को स्वीकार करना कई नई सच्चाइयों पर आधारित था। शीत युद्ध खत्म हो चुका था। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और ज्ञान आधारित नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसके बढ़ते महत्व की भी उसे अमेरिका के नजदीक लाने में भूमिका रही। एशिया में स्थायित्व बनाए रखने में भारत का रणनीतिक महत्व बुश प्रशासन के सामने शुरू से ही स्पष्ट था।

बुश प्रशासन ने भारत को अपने रणनीतिक सिद्धांत में भागीदार बनाने के लिए दशकों पुरानी अमेरिकी नीति की महत्वाकांक्षी समीक्षा शुरू की। जल्द ही जाहिर हो गया कि अमेरिकी और भारतीय नेता एक ही ढंग से सोच रहे थे और स्वतंत्रता, समृद्धि व सुरक्षा पर साझा प्रतिबद्धता के आधार पर नई साझेदारी बना रहे थे।

शुरुआती संकेत उत्साहजनक थे। अमेरिकी सरकार ने सीटीबीटी या अन्य किसी तरह के परमाणु संदर्भ का जिक्र किए बगैर भारत के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध हटाने का वादा किया। इस वादे में यह आश्वासन निहित था कि परमाणु क्षेत्र के निर्यात पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। भारत ने भी एक मई, 2001 को बुश द्वारा घोषित राष्ट्रीय मिसाइल प्रतिरक्षा कार्यक्रम की पुष्टि का ऐलान कर अपना रुख नरम किया। नए प्रशासन की ओर से सबसे पहले भारत यात्रा पर आने वाले विदेश उप-मंत्री रिचर्ड आर्मिटेज थे। उनकी यात्रा और तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह के वाशिंगटन दौरे की सफलता से भारत-अमेरिकी संबंधों में ''खुशनुमा एहसास'' की शुरुआत हुई। यह एहसास 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के खिलाफ हुए आतंकवादी हमलों के बाद मजबूत हुआ।

जहां भारत-अमेरिकी संबंधों ने खुद-ब-खुद नया जीवन हसिल किया है, वहीं यह भी सच है कि दोनों के अधिकारिक संबंधों के ढीले दौर में दोनों देशों के लोगों के बीच आपस में मजबूत संपर्क रहे हैं। अमेरिकी सपना कई भारतीयों को उत्साहित करता था और आज अमेरिका में बीस लाख से अधिक भारतीय हैं, जो मैक्सिको के बाद दूसरा सबसे बड़ा वैध आप्रवासी समूह है। अमेरिका में विदेशी छात्रों के समूह के मामले में भारतीय छात्रों ने चीनियों को पीछे छोड़ दिया है और अमेरिकी कांग्रेस में इंडियन कॉकस किसी भी देश के मुकाबले अमेरिकी विधि-निर्माताओं का सबसे बड़ा मित्र समूह है।

जॉन विलकार्ट

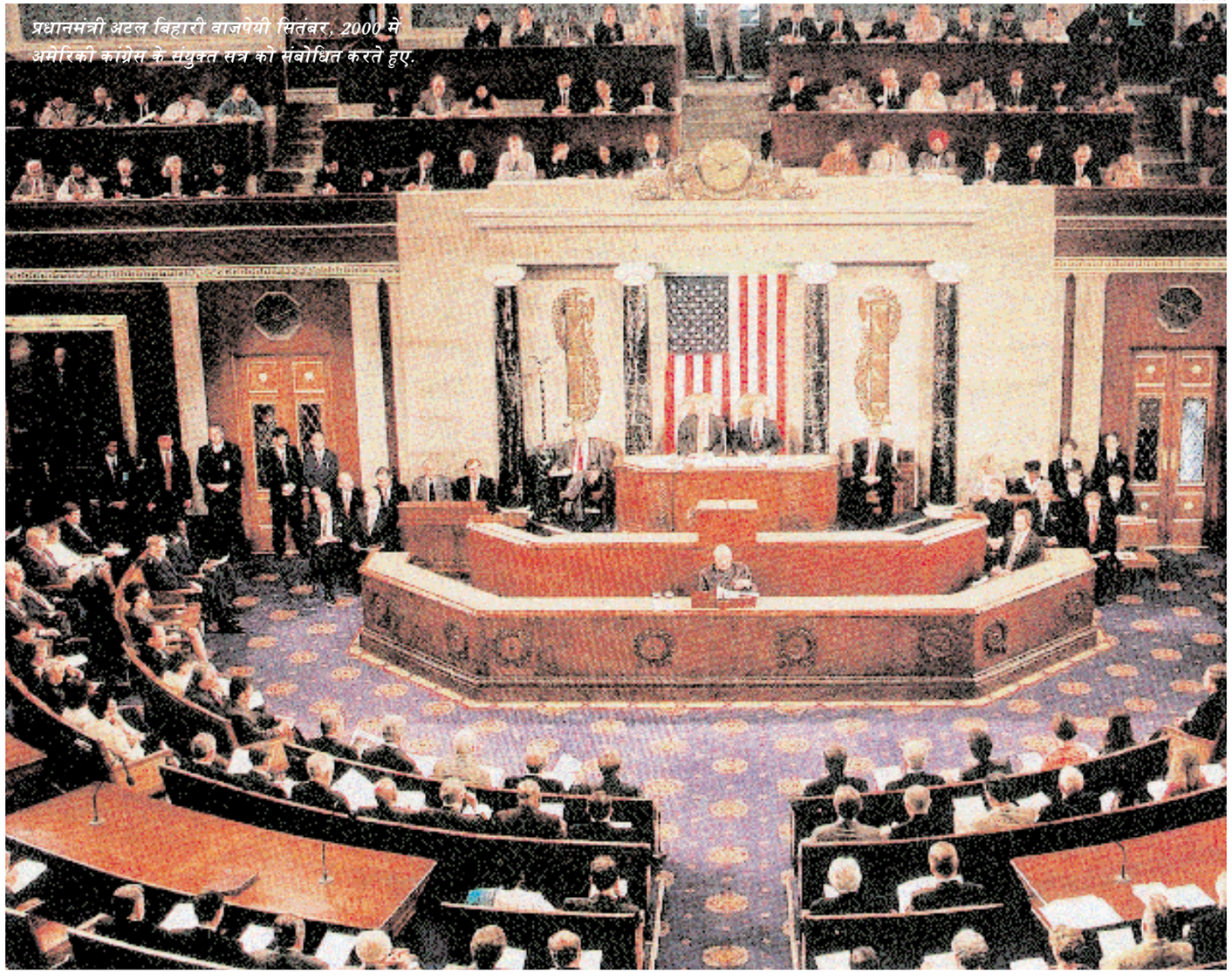

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सितंबर, 2000 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए.

भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ ही अमेरिकी कंपनियों ने इंडिया इंक. के साथ लाभकारी संबंध बना लिए हैं और दोतरफा व्यापार बढ़ रहा है। हालांकि भारतीय बाजार में पहुंच और टैरिफ़ की बाधाएं अभी भी हैं, जिन पर धीरे-धीरे ध्यान दिया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी और सेवाएं स्पष्ट रूप से आर्थिक संबंधों की अगुआ रही हैं और कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत की विशाल व कुशल ज्ञान क्षमता का लाभ उठाया है। यहां तक कि सिलिकान वैली की नई आईटी कंपनियों और भारत में अमेरिकी आईटी कंपनियों को प्रवासी भारतीय चला रहे हैं, वहीं कारोबार के समुद्रपारीय मॉडल को लेकर राजनैतिक बहस छिड़ी हुई है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग तक फैले हुए इन जटिल, बहुस्तरीय संबंधों में कॉल सेंटर, हाइ एंड सॉफ्टवेयर और अमेरिकी कंपनियों के लिए उत्पाद विकास करना शामिल है।

अमेरिकी अधिकारियों ने देखा है कि अमेरिकी बाजार भारतीय फर्मों और उनके उत्पादों के लिए ज्यादा खुला हुआ है, जबकि अमेरिकी व्यापार और निवेश के लिए भारतीय बाजार इतना खुला नहीं है। और बाजार में पहुंच के मसलों पर अभी भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टिना रोक्का ने कहा, ''हालांकि हम भारत के सबसे बड़े व्यापार साझीदार हैं पर हमारा दोतरफा व्यापार जितना हो सकता था, उससे भी कम है।'' उन्होंने कहा, ''उस स्थिति में सुधार हमारा प्राथमिक उद्देश्य है।''

सदी के अंत तक भारत और अमेरिका कई तरह के मामलों में गहनता से सहयोग कर रहे थे। इन मामलों में वैश्विक सुरक्षा, फारस की खाड़ी, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, एचआईवी-एड्स, आतंकवाद की रोकथाम, साइबर सुरक्षा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, और महाविनाश के हथियारों का प्रसार शामिल है। इस बीच, मैक्डोनल्ड भारत की पसंदीदा 'भारतीय' फास्टफूड श्रृंखला बन चुकी है और सिएटल ने एक क्रिकेट टीम बनाई है। हिंदी फिल्में अमेरिका में फिल्माई जा रही हैं और लोगों के बढ़ते आपसी संपर्क सुधरते रिश्तों का पैमाना बन रहे हैं। इस नई गतिशीलता की एक नायाब मिसाल चित्रेश दास हैं जो सैनफ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में भारतीय कथक नृत्य सिखाते हैं और जिन्होंने उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा कथक संस्थान स्थापित किया है। इस बदलाव ने संबंधों के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित किया है। अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी (यूएसएड) आगरा में ताज ट्रेपेज़ियम क्षेत्र के आसपास परिवेश में सुधार

के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और अमेरिका दूतावास परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को छोटी सहायता राशियां दे रहा है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हों।

तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा ''हाल के समय में भारत-अमेरिकी बातचीत का दायरा और उसकी निरंतरता खासी बढ़ी है। पर सबसे अहम यह है कि वार्ता का माहौल बदला है। अब हम एक-दूसरे से भरोसे के साथ और सच्चे दोस्त की तरह बात करते हैं। सम्मान और समानता पर आधारित यह संवाद इसलिए सफल है कि हमने यह बात जान ली है कि हमारे बीच हितों को लेकर कोई बुनियादी टकराव नहीं है।''

शिप्रा दास

भारत में अमेरिका के राजदूत डेविड सी. मलफोर्ड सीआईआई में बोलते हुए

अमेरिका और भारत के बदलते रिश्ते कई क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में 9/11 की घटनाओं के बाद नया स्तर हासिल किया गया है। यह सिलसिला महज सूचनाओं के आदान-प्रदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद पर विचारों की एकरूपता भी बढ़ी है।

तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने सहयोग के क्षेत्र को यह कहते हुए स्पष्ट किया, ''हमने पहली बार वास्तविक रक्षा सहयोग की शुरुआत की है। हमारी सशस्त्र सेनाओं में संपर्क स्थापित हुआ है और नियमित अभ्यास होते हैं और बढ़ती जटिलताओं पर आदान-प्रदान होता है। आतंकवाद, पारराष्ट्रीय अपराध और साइबर अपराधों पर हमारी समान चिंताओं ने हमें इन क्षेत्रों में भी संबंध कायम करने के लिए प्रेरित किया है।'' सहायता के क्षेत्र में भी संबंधों ने नया मोड़ लिया है क्योंकि यूएसएड अब विकास सहायता देने के पुराने तरीके अपनाने की बजाए प्रौद्योगिकी में साझीदारी और स्थायी क्षमताओं के निर्माण में अधिक शामिल है।

दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर हुए दौरों की संख्या से यह बात सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है। पिछले छह साल में कैबिनेट स्तर के तथा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इधर से उधर आते-जाते रहे हैं, जबकि पर्यटक, शोधार्थी और व्यापार जगत के लोग भी बड़ी संख्या में भारत से आते और जाते रहे हैं।

11 सितंबर 2001 के हमलों ने भारत और अमेरिका के बीच बनी नई समझ को अगले स्तर पर पहुंचाया। हमलों के तुरंत बाद भारत ने—इस कांड में भारतीय मूल के करीब 250 लोग मारे गए—आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सरकार को अपनी बिना शर्त मदद देने, यहां तक कि भारतीय सैन्य सुविधाओं के इस्तेमाल के प्रति आश्वस्त किया। अफगानिस्तान में ऑपरेशन एनड्यूरिंग फ्रीडम के दौरान भारतीय नौसेना ने मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की रक्षा और अपनी निगरानी में उनको ले जाने का महत्वपूर्ण मिशन संभाला। इस अमूल्य योगदान के कारण अमेरिकी जहाजों को

रॉयटर/लैरी डाउनिंग

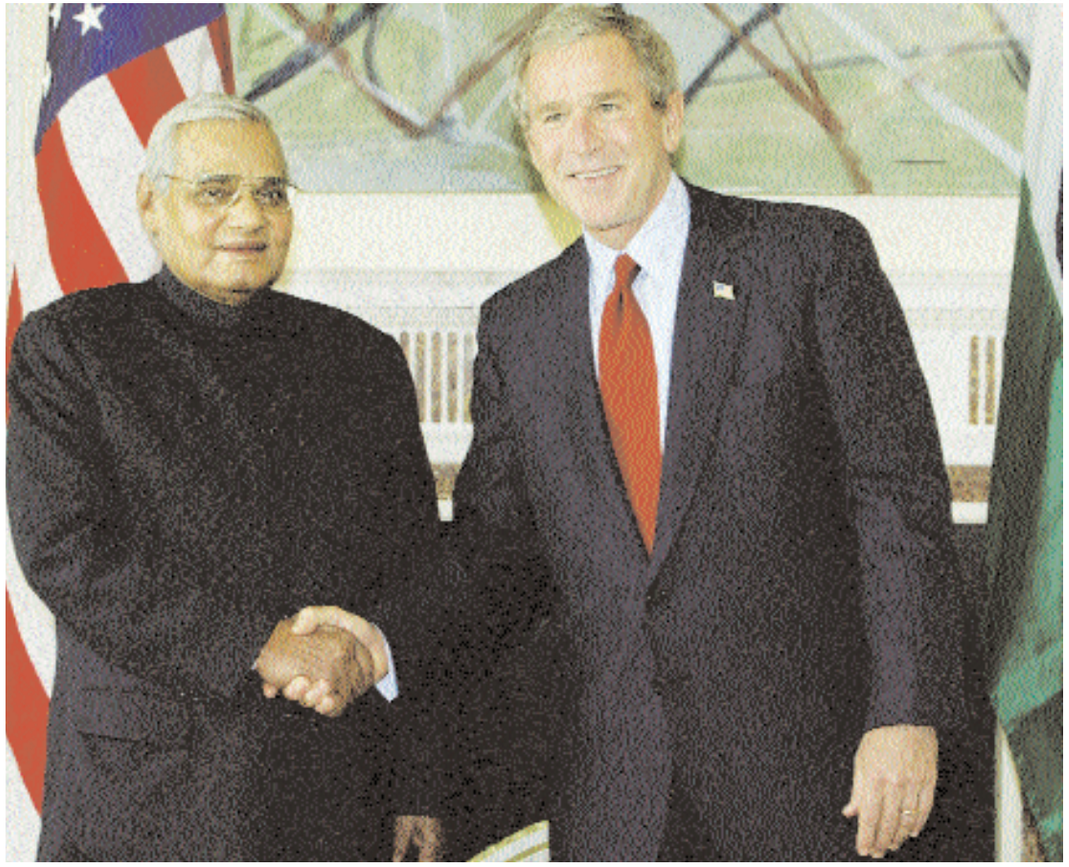

राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विश्व शांति और समृद्धि के साझा नजरिए से अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी का विस्तार हुआ।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दूसरी वैश्विक प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल गया। इतना ही नहीं, अमेरिकी नौसैनिक जहाजों को अस्थायी तौर पर रुकने और ईंधन भरने के लिए भारतीय बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत देकर भारत ने अमेरिकी नौसेना को अपने अंतर-सामुद्रिक अभियान जारी रखने के लिए जरूरी आपूर्ति संबंधी सहायता मुहैया कराई। अमेरिकी वायु सेना के विमानों को अपने क्षेत्र से उड़ने की अनुमति देना भी भारत सरकार का एक और बड़ा योगदान था, जिससे अभियान की योजना बनाने वालों के अनगिनत घंटे बचे।

जब आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई चली तो अमेरिका और भारत के बीच व्यापक सैन्य संबंध का विकास और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इसका मकसद एशिया में स्थिरता बरकरार रखना था। सन् 2002 के बाद से ही दोनों सेनाएं सैन्य अभ्यासों, आदान-प्रदान, संयुक्त सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के जरिए इतने गहन संपर्क में रही हैं, जितनी पहले कभी नहीं रहीं। अमेरिका भारत के लिए प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है, इस स्थिति की कुछ साल पहले तक कल्पना ही की जा सकती थी। सीमा पार से भारत को आतंकवादी खतरों की बात स्वीकार करते हुए अमेरिका ने उसे अत्याधुनिक सीमा प्रबंध प्रणालियां बेचने की पेशकश की। साथ ही, आतंकवाद निरोधक प्रयासों में खुफिया जानकारी के

1998

■ भारत ने पोखरण में पांच परमाणु परीक्षण किए।

■ पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए।

■ ग्लेन संशोधन के तहत अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए।

■ जसवंत सिंह-स्ट्रोब टालबोट के बीच पहली अमेरिका-भारत रणनीतिक वार्ता।

1999

■ रणनीतिक बातचीत जारी।

■ भारत ने परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार किया।

■ अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार सत्ता में आई।

■ करगिल पर भारत-पाक संघर्ष। प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ की वाशिंगटन यात्रा के बाद सेनाओं की वापसी।

2000

■ भारत-अमेरिका का आतंकवाद से निबटने के लिए साझा कार्यदल बनाने का फैसला।

■ राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए।

■ भारत और अमेरिका ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम गठित किया।

■ वाजपेयी की वाशिंगटन यात्रा, कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। हथियारों के नियंत्रण, आतंकवाद और एड्स पर सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

2001

■ राष्ट्रपति बुश ने पदभार संभाला।

■ राष्ट्रपति बुश ने रॉबर्ट डी. ब्लैकविल को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की।

■ बुश प्रशासन के नेताओं से मिलने वालों में जसवंत सिंह पहले भारतीय नेता बने।

■ भारत ने कहा कि बुश का मिसाइल प्रतिरक्षा प्रस्ताव 'महत्वपूर्ण और दूरंदेशी' है।

■ मिसाइल प्रतिरक्षा पर बात करने के लिए विदेश उपमंत्री रिचर्ड आर्मिटेज भारत आए।

■ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र वाशिंगटन गए। उच्चस्तरीय दौरों की संख्या बढ़ी।

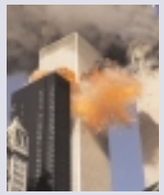

■ न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर 9/11 के आतंकवादी हमले।

■ वाजपेयी ने कहा, ''मैंने राष्ट्रपति बुश को आश्वस्त किया है कि हम इस अपराध की जांच में सहयोग तथा आतंकवाद फिर कभी सफल न हो पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए भी तैयार हैं।''

■ राष्ट्रपति बुश ने भारत के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध हटाए।

■ भारत-अमेरिका ने कानून प्रवर्तन और आतंकवाद के खात्मे में सहयोग के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस संधि पर हस्ताक्षर किए।

■ वाजपेयी वाशिंगटन में राष्ट्रपति बुश से मिले। उन्होंने अमेरिका-भारत आर्थिक वार्ता की घोषणा की।

■ पांच साल बाद अमेरिका और भारत ने रक्षा नीति समूह फिर शुरू किया।

■ पांच सशस्त्र व्यक्तियों का भारत के संसद भवन पर हमला, 14 मारे गए।

■ अमेरिकी-भारतीय नौसेनाओं ने पहले साझा सैन्य अभ्यास में अरब सागर में संयुक्त तलाशी, बचाव अभियान चलाया।

■ राष्ट्रपति बुश ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं को टेलीफोन किया, पाकिस्तान से कहा कि वह ''भारत को नुक्सान पहुंचाने की कोशिश करने वाले, पाकिस्तान को कमजोर करने और लड़ाई भड़काने वाले उग्रवादियों को खत्म करने के लिए और भी मजबूत और निर्णायक कदम उठाए।''

2002

■ अमेरिका और भारत बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य सहयोग में संलग्न।

■ अमेरिका 12 एएन-टीपीक्यू-37 फायर फाइंडर काउंटर बैटरी रडार भारतीय सेना को देने को राजी।

■ अमेरिका दक्षिण एशिया में तनाव घटाने में मदद करने के लिए सक्रिय हुआ।

■ एनआरसी के अध्यक्ष रिचर्ड मेसर्वे नागरिक परमाणु सहयोग पर बातचीत करने भारत आए।

2003

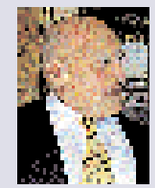

■ विदेश उपमंत्री आर्मिटेज, द. एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री रोक्का भारत- पाकिस्तान की द्विपक्षीय वार्ता में मदद व तनाव घटाने के प्रयासों के तहत द. एशिया यात्रा पर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र सुरक्षा मसलों पर चर्चा के लिए वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से मिले।

■ अमेरिका और भारत ने नया इंडिया-यूएस ग्लोबल इश्यूज़ फोरम शुरू किया।

■ उच्च प्रौद्योगिक सहयोग समूह बना।

■ वाजपेयी ने कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ ''दोस्ती का हाथ'' बढ़ाया।

■ सीआईसीएस जनरल मायर्स भारत यात्रा पर।

2004

■ अमेरिकी विदेश विभाग ने इस घोषणा का स्वागत किया कि भारत और पाकिस्तान के नेता समग्र वार्ता शुरू करेंगे।

■ प्रधानमंत्री वाजपेयी और राष्ट्रपति बुश ने रणनीतिक साझेदारी में अगले कदमों की घोषणा की।

■ अमेरिका के नए राजदूत डॉ. डेविड मलफोर्ड ने नई दिल्ली में कार्यभार संभाला।

■ विदेश मंत्री पॉवेल, स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्री थाम्पसन और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जोएलिक सहित वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी भारत आए।

■ भारतीय मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को सत्ता सौंपी और डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अमेरिकी अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी को बधाइयां दीं और मजबूत साझा संबंध बनाने की प्रक्रिया जारी रखने की इच्छा जताई।

आदान-प्रदान ने दोनों देशों को फायदा पहुंचाया है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की जंग के भारत की लड़ाई से भी गहरे जुड़े होने का तथ्य इससे भी जाहिर हुआ कि अमेरिका ने न सिर्फ लश्कर-ए-तय्यबा जैसे आतंकवादी गुटों पर प्रतिबंध लगाया, बल्कि भारत के माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को भी प्रतिबंधित कर दिया।

जिस प्रकार 9/11 ने अमेरिका-भारत संबंधों की शक्ल बदली, उसी तरह उसने पाकिस्तान से जारी रहने वाले सीमा पार आतंकवाद को रोकने की जरूरत को भी रेखांकित किया। सन् 2002 में जब भारत और पाकिस्तान संघर्ष की तरफ बढ़ रहे थे तो अमेरिका यह संकट दूर करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ था। विदेश मंत्री पॉवेल और उनके डिप्टी रिचर्ड आर्मिटेज दोनों ही इस्लामाबाद और नई दिल्ली को यह साफ-साफ संदेश देने के लिए गए कि अमेरिका भारत के खिलाफ सीमा पार से जारी आतंकवादियों की घुसपैठ हमेशा के लिए खत्म कराना चाहता है। अमेरिकी सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब भारत और पाकिस्तान अपने मतभेद खत्म करने के लिए काम करेंगे तब अमेरिका शांति कायम करने वाले दोनों पक्षों का पक्का दोस्त और समर्थक बना रहेगा और दोनों से अपने स्तर पर मजबूत दोतरफा संबंध बनाना जारी रखेगा।

अमेरिकी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच इसके बाद शुरू हुई रिश्तों की गर्माहट का तहेदिल से स्वागत किया। रोक्का ने कहा, ''अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में समानांतर सुधार को 'संघर्ष समाधान के त्रिकोण' में बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम खुद को मध्यस्थ के रूप में नहीं थोपना चाहते, इसकी बजाए हम उस भरोसे को आजमाना चाहते हैं, जो हमने दोनों पक्षों के साथ बनाया है जिससे कि वे शांतिपूर्ण तरीकों से सद्भाव की तरफ बढ़ें।'' अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता रिचर्ड बाउचर ने जनवरी, 2004 में कहा, ''हमें खुशी है कि दोनों पक्ष भविष्य की बातचीत का खाका लेकर आगे आए हैं। हमें यह भी प्रसन्नता है कि वे बातचीत आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।''

अमेरिकी-भारतीय संबंधों का कायापलट जारी है। हालांकि अभी तक इसमें काफी तेजी से प्रगति हुई है, फिर भी इन आपसी संबंधों के आवेग और गुणवत्ता को लगातार मजबूत किए जाने की जरूरत है। इससे आर्थिक संबंधों, उच्च प्रौद्योगिकी और अन्य व्यापार जैसे मसलों में और भी प्रगति होगी। साथ ही राजनैतिक लाभ के लिए संरक्षणवादी प्रवृत्तियां न्यूनतम करने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता से संबंधों की गति तथा संभावनाएं भी निर्धारित होंगी।

आखिरकार 'स्वाभाविक सहयोगी' का मुहावरा मुख्य रूप से अमेरिका और भारत के बुनियादी सिद्धांतों का जिक्र करता है: विशाल और क्रियाशील ऐसे लोकतंत्र जो राजनैतिक और आर्थिक आजादी के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दोनों देशों के संबंध कहां तक पहुंच सकते हैं, इस बारे में विदेश मंत्री पॉवेल का निष्कर्ष है: ''आगे बढ़ता, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक भारत विश्व मंच पर अपना स्थान बना रहा है और अमेरिका उसके साथ घनिष्ठ साझीदार के रूप में काम करने का इच्छुक है। मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में अमेरिका-भारत के संबंध उतने ही गहरे और जीवंत होंगे जैसे बॉलीवुड की कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ती है। तय है कि इसमें कुछ मोड़ और घुमाव भी होंगे और पात्रों के लिए कुछ चुनौतियां भी उभरेंगी जिन पर उन्हें काबू पाना होगा। पर मुझे इसमें संदेह नहीं कि इसके बाद भारत-अमेरिका और विश्व समुदाय के लिए खुशी के नतीजे सामने आएंगे।